Naxalism collapse in Bihar

(बिहार में नक्सलवाद का पतन)

Pappu Thakur[a] ; Dr. Narad singh[b]

[a]Research Scholar, Faculty of Social Sciences,V.K.S. University, Ara-Bihar,

[b] Head of Department, History Department,V.K.S. University, Ara-Bihar

DOI: 10.52984/ijomrc1203

सारः

नक्सलीय समस्या हमारे देश के लिए बड़ा आंतरिक खतरा बन गया है। खासकर 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणियों के बाद, यह एक चिंता का विषय बन गया है और साथ ही अकादमिक बहस का विषय भी है। इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर और गहनता से संबोधित करने के लिए नवीन विचार और नए सिरे से योजना बनाई गई है। इस पृष्ठभूमि में, मध्य बिहार का एक मामला अध्ययन इस मुद्दे पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रासंगिक हो जाता है। यह एक स्थापित तथ्य है कि बिहार में नक्सलवाद ने मध्य बिहार के माध्यम से अपना रास्ता बनाया था। जब काउंटरिंसर्जेंसी तंत्र ने पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद के पहले बुलबुले को कुचल दिया, तो उसे मध्य बिहार में अपना प्रजनन क्षेत्र मिला। मध्य बिहार में बार–बार नरसंहार और नक्सल आतंक देश के लिए 1980 और 1990 के दशक में चिंता का विषय बन गया। यह तर्क देता है कि बदलती सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के साथ–साथ अन्य कारकों ने मध्य बिहार में माओवादी लोकप्रियता और ताकत को व्यापक रूप से प्रतिबंधित कर दिया।

संकेतः नक्सलवाद, सामाजिक परिवर्तन, आसद्वार परियोजना

परिचयः

झूलन देवी संध्या ब्लॉक के अंतर्गत पांडुरा गाँव की पहली महिला ऐसी नक्सली नेता थीं। उन्होंने सन् 2000 के पंचायत चुनाव में नक्सली उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। पंडुरा पंचायत के लिए माओवादी मुखिया चुनने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। लेकिन बहुत जल्द वही फायर ब्रांड बूढ़ी महिला माओवादी ताकतों के खिलाफ हो गई। झूलन देवी ने कहा, *"सभी माओवादी नेता राजनीतिक ठग हैं। वे सवर्ण सामंती से भी बदतर हैं। वे हिंसा और हत्या का उपयोग सामाजिक न्याय लाने के लिए नहीं बल्कि अपने निहित स्वार्थों के लिए करते हैं। "* झूलन देवी की तरह, अन्य लोग जो कभी नक्सली के हमदर्द और प्रमोटर हुआ करते थे लेकिन उनके खिलाफ हो गए हैं। जिसने बिहार में माओवादी ताकतों की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन कर दिया हैं।

बिहार से नक्सलवादी घटनाओं में नाटकीय गिरावट आई है। एक से अधिक कारकों ने इस गिरावट में अपना योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भोजपुर पटना, गया, अरहबद, अरवल, भभुआ, रोहतास और जहानाबाद में तेजी से गिरावट देखी गई है। परन्तु बिहार के कई अन्य जिलों में नक्सल संगठनों का विस्तार हुआ है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शेहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों सहित नेपाल की सीमा से लगे उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में अतिवाद की स्थिति रही है। धीरे धीरे नक्सलियों ने शाहरसा, बेगूसराय और वैशाली और उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बढ़ाया है।

बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत भोजपुर से हुई। एकवारी गाँव ने नक्सलवाद की होड़ को शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। जिसकी चिंगारी आसपास के जिलों पटना, जहानाबाद, गया और तक फैल गई। नक्सल आंदोलन की शुरुआत अपने ही गुस्से और सामाजिक न्याय के घोर उल्लंघन से हुई। भोजपुर में कई बड़े जमींदार नहीं थे। लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने भूमि सुधार के लिए बहुत विषम परिस्थितियों का निर्माण किया। जदीशपुर और डुमराव के अलावा, केशात, चौगाई, कसाप के जमींदार अन्य जिलों में मौजूद थे। चरम सामाजिक और आर्थिक द्वंद्ववाद ने माओवाद को मध्य बिहार में फलने के लिए सौहार्दपूर्ण उपजाऊ आधार प्रदान किया। ऐसे कई कारण हैं जिनकी पहचान की जा सकती है जिसके कारण बिहार से नक्सलवाद धीरे–धीरे समाप्त हो गया। जिसका विशद विवेचन निम्न वर्णित है–

समाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तनः

मध्य बिहार में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। मध्य बिहार के विभिन्न जिलों में दलितों और निचली जातियों का अनुपात अधिक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिहार के 30 जिलों को देश के पिछड़े जिलों के रूप में निरूपित किया गया है। मध्य बिहार के लगभग सभी जिले इस श्रेणी में आते हैं। ये जिले हैं भोजपुर, जहानाबाद, रोहताश, पटना और गया। इन जिलों में उच्च जातियों की आबादी का प्रतिशत लगभग 12 प्रतिशत है। निम्न जाति का हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत है। लेकिन इन जिलों में दो प्रमुख पिछड़ी जातियों यादव और कुर्मी की आबादी का हिस्सा लगभग 16 प्रतिशत है। मध्य बिहार में नक्सल आंदोलन ने जाति के पहिये के द्वारा अपना कदम रखा। मुख्य रूप से यादव को उच्च जाति के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए पहचाना गया था। एम.सी. सी. के संस्थापक *कनई चटर्जी* ने माओवादी आंदोलन के ध्वजवाहक के रूप में यादव समुदाय को चुना। मध्य बिहार में बदलते सामाजिक ताने–बाने की दो विपरीत घटनाएं हैं। एक जहानाबाद जिले के मथिया गाँव का है, जहाँ अक्टूबर 1989 में उच्च जाति के पुरुषों द्वारा निम्न जाति के युवाओं से जोड़ कर देखा जाता है। वास्तव में, धोबी जाति (धोबी के आदमी) के द्वारा तथाकथित सामाजिक व्यवस्था की अवज्ञा की गई। वे कुर्सी पर बैठे रहे और खड़े नहीं हुए जबकि ऊंची जाति के लोग उनके पास से गुजर रहे थे।

भोजपुर जिले के संधेश ब्लॉक में 12 पंचायत हैं। हर पंचायत में एक छठ पूजा समिति होती है। छठ पर्व बिहार का सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक त्योहार है। कुछ दशक पहले, छठ की समिति में एक पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि होना अकल्पनीय था। परन्तु वर्तमान में आश्चर्यजनक रूप से सभी पंचायत में अलग–अलग जातियों को समिति में शामिल किया जा रहा है। जिससे सामाजिक समरसता का संचार हो रहा है। सामाजिक व्यवस्था के इस नए रीमेक ने नक्सलबादियों को चुनौती दी है। निचली जातियों की जनसंख्या का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों का 18 प्रतिशत समाज में समायोजित है। गाँव में हर गतिविधि का नेतृत्व लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता है जिसमें विभिन्न जातियाँ शामिल होती हैं। बिहार में नक्सली आंदोलन ने सामाजिक और आर्थिक मामलों में शोषणकारी संबंधों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इज्जत (गरिमा या सम्मान) एक महत्वपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता है जिसे उसने बहाल करने का प्रयास किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सली आंदोलन उच्च जातियों के दिमाग के सेट को बदलने और दलितों की मानवीय गरिमा को बहाल करने में प्रभावी रहे हैं।

नक्सल विरोधी बलों का अंतः

वर्तमान बिहार में उच्च जातियों के कई ऐसे युवा हैं, जो अपने गांवों में संघर्षपूर्ण स्थिति नहीं लाना चाहते हैं, जो हिंसा और आतंक को बढ़ावा देता है। नक्सल आतंक की पृष्ठभूमि में बिहार में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है। रणवीर सेना, ऊंची जातियों के लिए अप्रासंगिक और पुरानी हो गई है। उदाहरण स्वरूप *जहानाबाद के पुष्पोत्तम सिंह ने नक्सल के खिलाफ लड़ने के लिए रणवीर सेना को चंदा (वार्षिक राशि) 100*0 रुपये देना बंद कर दिया। इसके दो कारण है एक तो वित्तीय संकट व दूसरा रणवीर सेना से मोहभंग था। रणवीर सेना के कमजोर पड़ने ने के कारण विहार में एक सामाजिक व्यवस्था का प्रार्दुभाव हुआ है, जो बिहार की अन्य जातियों खासकर अनुसूचित जातियों को समायोजित करने में काफी हद तक समावेशी रही है। यह विश्लेषण करना बहुत दिलचस्प है कि राज्य में उच्च जातियों के प्रभाव का अस्तित्व कैसे समाप्त हो गया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में नक्सलियों के समूह को शामिल करने और उच्च जातियों से संबंधित भूमि की रक्षा करने के उद्देश्य से निजी जातियों या सेनाओं का गठन करके उच्च जातियों के भू–स्वामियों ने जवाबी कार्रवाई की। राजपूतों ने 1969 में *कुनेर सेना* का गठन किया, 1988 में *सूर्य सेना* का गठन किया। ब्राहमणों ने *गंगा सेना* की स्थापना की और भूमिहारों ने 1981 में *ब्रह्मर्षि सेना* और 1990 में *सवर्ण मुक्ति मोर्चा* का गठन किया। 1980 के दशक तक नक्सली समूहों और अभिजात वर्ग के बीच दुश्मनी बढ़ने के कारण, जाति और सामुदायिक एकता में गहरा ध्रुवीकरण हुआ। इसके चलते रणवीर सेना की शुरुआत हुई।

रणवीर सेना का जन्म 1994 में भोजपुर के सभी उच्च जाति के जमींदारों के समर्थन से हुआ था। इसने पहली बार जुलाई 1996 में *बथानी टोला* पर हमले के साथ अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं। रणवीर सेना प्रमुख *ब्रह्मेश्वर सिंह,* 36 नरसंहारों के पीछे का मास्टरमाइंड, जिसने पिछले छह वर्षों में कम से कम 400 लोगों की जान ले ली, रणवीर सेना दलितों के कई नरसंहारों में शामिल रही है। इनमें लक्ष्मणपुर–बाथे, मियांपुर (36), शंकरबिघा (18), सरथुआ (8), नागरी (10), हैबसपुर (15), बथानी थोला (21) और संतानी (13) की घटनाओं से संबंधित मामले शामिल हैं। ये गाँव मध्य बिहार के भोजपुर, जहानाबाद और गया जिलों में स्थित हैं। बिहार का इतिहास, तीन दशकों से अधिक समय से, नरसंहारों से भरा हुआ है। जो विभिन्न जमींदार सेनाओं और इसके विपरीत दलित जातियों के ग्रामीण गरीबों के नरसंहार से सम्बन्धित है।

वर्तमान में सवर्णों में गरीबी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। जिससे उच्च जातियों के बीच जमींदारों की संख्या में गिरावट आई है। जिसके कारण जीवकोपार्जन एवं अगली पीढ़ी को हिंसक परिस्थितियों से बचाने के लिए कई गांवों के लोग शहरों में चले गए है। इसने उच्च जातियों के समग्र ढांचे को कमजोर कर दिया है तथा केंद्रीकृत शक्ति संरचनाएं ध्वस्त हो गईं। वर्तमान में उच्च जातियों की युवा पीढ़ी जबरदस्त आर्थिक कठिनाई से गुजर रही है। संयुक्त परिवार बंट गए है। घर के विभाजन ने भूमि के स्वामित्व को सिर की गिनती पर निचोड़ लिया है। सरकारी नौकरियां बहुत कम है, इस सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन ने राज्य में उच्च जातियों से

जमींदारी की स्थिति को कमजोर कर दिया है। इससे सभी जातियों को एक समूह में समायोजित करने और तदनुसार काम करने के नए सामाजिक क्रम की शुरुआत हुई। नए सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत ने न केवल उच्च जातियों के प्रभाव को अप्रासंगिक बना दिया बल्कि नक्सल संगठनों को भी चुनौती दी।

बिहार में नक्सल समूहों ने अनुसूचित जातियों से सबसे बड़ा हिस्सा भर्ती किया है। परस्पर विरोधी सामाजिक व्यवस्था ने अनुसूचित जातियों को अपराधों के क्षेत्र में धकेल दिया था। उनमें से कई नक्सली समूहों में शामिल होकर अपराधी बन गए और अपने परिवारों को गांवों में पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया। कई मामलों में नया सामाजिक क्रम अन्य सभी जातियों को स्थान प्रदान करता है। इसने बिहार में नक्सल समूहों के लगातार विस्तार वाले चरणों को चुनौती दी है। अनुसूचित जातियों की युवा पीढ़ी अपने परिवारों के साथ अपने गाँवों के भीतर अपनी खुशी और आर्थिक गतिविधियों में लिप्त रहना चाहते है। वे पुलिस बल द्वारा शिकार नहीं होना चाहते और न ही नक्सल संगठनों द्वारा जबरदस्ती किया जाना चाहते हैं। राज्य और केंद्र सरकार की नई योजनाओं के कार्यान्वयन ने एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाने में मूल्यवान भूमिका निभाई है। जिसके कारण सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला है एवं माओवादी सोच पर आघात किया है।

सामाजिक उद्यम द्वारा नक्सल आंदोलन को चुनौतीः

जमीनी स्तर पर व्यापक शोध से कई अलग–अलग दृष्टिकोणों का पता चलता है। ज्ञात तथ्यों में से एक नक्सली ताकतों के मूक हत्यारे की भूमिका के बारे में ध्यान में आया है। जो सामाजिक उद्यमियों की भूमिका की ओर इंगित करता है। बिहार का एक मामला अध्ययन इस तथ्य को बढ़ाता है। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि सामाजिक उद्यमी नक्सल आउटफिट को कैसे हरा सकते हैं, उनके खिलाफ युद्ध किए बिना। हाल ही में बिहार के एक सामाजिक उद्यमी, निडान के *श्री अरबिन्द सिंह* ने 2009 में विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन में वर्ष का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार जीता। निदन बिहार के विभिन्न जिलों में काम करता है। इसके लक्षित समूह दलित और समाज के बेहद हाशिए पर रहने वाले लोग हैं। निडान की यात्रा, बहुत बारीकी से, स्वयं सहायता समूहों के साथ शुरू हुई। 1996 में पटना में तीन समूहों से, प्रारम्भ हो कर, वर्तमान में (2009 के अनुसार) लगभग 57,433 की कुल सदस्यता के साथ छह जिलों में फैले 23 ब्लॉकों में लगभग 4800 है। लगभग 72 फीसदी एसएचजी ग्रामीण क्षेत्र में हैं। एसएचजी की लगभग 62 प्रतिशत सदस्यता अनुसूचित जातियों की है। सामूहिकता की यह प्रक्रिया सामाजिक पूंजी उत्पन्न करती है, जो दलित समुदाय के अधिकांश गरीबों की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। निदान की पहलों ने समाजों के हाशिये के वर्गों के लिए अच्छे और स्थिर जीवन के बारे में जागरूकता अभियान उत्पन्न किया। इसने राज्य के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दलितों की एक मजबूत आवाज विकसित की है। स्वयं समूहों का निर्माण और उन्हें बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जोड़ने से गरीबों के जीवन में जादुई परिवर्तन आया है। इसने उन्हें कई सबक सिखाए। पहला, समाज में शांति और सहयोग विकास की आदर्श स्थिति है। नक्सलियों की हिंसक पद्धति उनके जीवन में कोई ठोस बदलाव लाने वाली नहीं है। वास्तव में, इसने उन्हें असुरक्षा की अधिक अनिश्चित स्थिति में धकेल दिया है। दूसरा, आमदनी के एकत्रीकरण ने एकजुटता और भाईचारे की भावनाओं को विकसित किया। उनके संकट के समय बैंक से मिले ऋण से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास पैदा हुआ। इसके अलावा, संगठन का संघ जो उनके प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है, ने समग्र समाज की आशा को जन्म दिया, जिसके पास हिंसा के लिए कोई जगह रिक्त नही है।

मजबूत लोकतान्त्रिक भावनाः

चारू मजुमदार के *'बंदूक के बैरल के तर्क'* और *कनु सान्याल* की किसी भी तरह से राजनीतिक सत्ता हथियाने का सिद्धान्त विफल साबित हुई है। वास्तव में, भूमिगत गतिविधियों और हिंसा पर उनकी अत्यधिक निर्भरता के कारण, नक्सली समूहों को वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक तुच्छ राजनीतिक बल के लिए कम कर दिया गया है। उनके पास भारतीय समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्ष में बलों के संतुलन को झुकाव के लिए किसी भी निर्णायक शक्ति की कमी है। भारतीय गरीबों की वर्ग एकजुटता का हमेशा एक नाजुक आधार रहा है और नक्सली इन वर्गों को नहीं जुटा पाए हैं। आज यह आम तौर पर स्वीकार किया जाने वाला विश्वास यह है कि नक्सलवाद आम लोगों के आर्थिक और सामाजिक अभाव में निहित है और राज्य अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करता है। मीडिया में ऐसी कई रिपोर्टें हैं, जो बताती हैं कि, बिहार में प्रभावित इलाकों में किसी भी विकास कार्य को अंजाम देने के लिए, ठेकेदारों को आवंटित धन का 30 प्रतिशत कमीशन नक्सलियों के स्थानीय क्षेत्र कमांडर को देना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में, नक्सली संग्रह सरकार द्वारा एकत्र किए गए वाणिज्यिक कर से कहीं अधिक है। अन्य रिपोर्टों के अनुसार, बिहार के कुछ हिस्सों में कई सरकारी अधिकारी क्षेत्र के नक्सलियों द्वारा उत्पन्न खतरे के कारण अपने कार्यालयों में भी नहीं जाते हैं। लेकिन सरकार के धन का उपयोग किया जा रहा है। जबरन वसूली का धंधा इतना लचर हो गया है कि कई क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और छोटे–मोटे अपराधियों ने नक्सलियों को पैसा दे दिया है। पैसे की लालच और विचारधारा की घटती भूमिका ने नक्सलवादी आंदोलन को जमीनी स्तर पर प्रभावित किया है। इसने कैडर बेस के बढ़ते अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है, जो बिहार में सबसे अधिक दिखाई देता है। आम कैडर, जिनके पास बहुत कम शिक्षा है और जिनमें उचित आवास का अभाव है, स्थानीय मुद्दों के साथ अधिक शामिल हैं, एक प्रवृत्ति जो नक्सली विचारधारा के खिलाफ है। अपने कब्जे में हथियारों के साथ, ये युवा, निचले–नक्सली नक्सली सामान्य हुड़दंगियों और अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं

करते हैं। जातिगत विचार और कुछ स्थानीय नक्सल नेताओं की आपराधिक पृष्ठभूमि भी एक शक्तिशाली, प्रभावशाली भूमिका अदा करती है।

ऊँची जाति से निम्न जाति को सत्ता केंद्र परिवर्तनः

मध्य बिहार के पांच जिलों के ब्लॉक के आकड़ों से पता चलता है कि एक विशेष जाति यानी यादव जाति के व्यक्तियों ने कुल बेची गई भूमि का लगभग 30 प्रतिशत खरीदा है। भूमि पर उच्च जाति की पकड़ धीरे–धीरे उच्च जाति से निम्न जाति तक हो गई। नतीजतन, यादव समुदाय ने माओवादी आंदोलन से दूरी बनाने की कोशिश की। एक बार जब यादव आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने खुद माओवादी हमले की आशंका जताई। अन्य पिछड़ी जातियों ने एक ही पंक्ति में सबसे ऊपर है। वास्तव में, अनुसूचित जाति समुदाय को भी नया सामाजिक सामंजस्य पसंद आया जो जातिगत प्रतिद्वंद्विता के चरम विरोधाभास से उभरा था।

संधेश की कहानीः

संधेश ब्लॉक में नक्सलियों का क्रमिक उन्मूलन देखा गया है। संधेश भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। संधेश ब्लॉक के अंतर्गत 11 पंचायतें हैं। संधेश ब्लॉक की पंचायतों में नक्सल प्रभुत्व के अंत का एक जमीनी स्तर दृ श्यमान होता है। बिहार में नक्सलवाद बिहार के दो ब्लॉकों से शुरू हुआ। संधेश उनमें से एक थी। एक अन्य समीपवर्ती ब्लॉक सहार था। सबसे महत्वपूर्ण कारक, जो नक्सल प्रभुत्व को खत्म करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ, वह था बिहार में पंचायत चुनाव। बालू प्रखंड में 2000 पंचायत चुनाव के तहत छह पंचायतों में मुखिया थे। दूसरा पंचायत चुनाव संधेश ब्लॉक में 2006 में आयोजित किया गया था। यह गांवों में माओवादियों की अलोकप्रियता का पहला महत्वपूर्ण संकेत था। इसने माओवादी नेताओं और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण दूरी बनाई।

माओवादी के खिलाफ सामाजिक सामंजस्य की प्रक्रिया संधेश ब्लॉक की कई पंचायतों में शुरू हुई। उन्होंने गांवों के विकास के लिए किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में निचली जातियों का सम्मान करना और उन्हें समायोजित करना शुरू कर दिया। सामाजिक व्यवस्था का यह नया रवैया नक्सलियों के सहानुभूति रखने वालों पर दबाव डालता है कि वे अपना रास्ता बदलें या गांवों को छोड़ दें। सामाजिक दबाव ने खेती करने के लिए कई नक्सलियों को बदल दिया और नक्सली संगठनों के साथ अपने सहयोग को खत्म कर दिया। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने संधेश ब्लॉक के तहत कई गांवों से नक्सलियों की संख्या को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। हार्ड कोर नक्सल नेताओं ने गांवों को छोड़ दिया। धीरे–धीरे संध्या ब्लॉक जिसमें 11 पंचायतें हैं, को नक्सल हिंसा से मुक्त कर दिया गया है। सूरज ढलने पर अब गांवों में दरवाजे बंद नहीं होते। लोग देर रात तक खुलेआम घूमते हैं। पंचायत राज व्यवस्था के तहत माओवादी नेताओं की भ्रष्ट प्रथाओं ने उनके असली रंग को उजागर किया। मुखिया के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, वे लोगों से कटे रहे। उनके द्वारा सभी तरह की कुप्रथा का पालन किया जा रहा था। उन्होंने पैसे का दोहन किया और अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया। जिससे माओवादी नेताओं की असली तस्वीर सामने आई। उच्च जातियों के खिलाफ नफरत की उनकी कैलिब्रेटेड योजना निचली जातियों के सामने आ गई। नक्सल रणनीति का उन्मूलन विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सामंजस्य लाया। वे एक नेता का चुनाव करने के लिए एक साथ आए जो गांवों के विकास के लिए काम कर सकने में सक्षम हो।

जहानाबाद में आसद्वार परियोजनाः

जहानाबाद डायट में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई पहलें शुरू हुई हैं जो दो दशकों से अधिक समय से नक्सल हिंसा के लिए चर्चा में बनी हुई हैं। लेकिन जहानाबाद में आसद्वार परियोजना की हालिया पहलों ने नक्सल आधार को एक बड़े स्तर पर गिरा दिया है। वर्तमान में जिले के पांच नक्सल प्रभावित पंचायतों में यह योजना चल रही है। ये सिकरिया, सेवनन, मंडेबीघा, सुरंगपुर– भवानीचक और जामुक, सभी जहानाबाद सदर ब्लॉक में हैं। इन पांच पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांवों में युद्धस्तर पर विकास गतिविधियों की सुगबुगाहट देखी जा रही है। राज्य सरकार ने असद्वार के तहत कल्याण योजनाओं का एक उदार पैकेज दिया है, जिसमें इन पंचायतों में सीमेंट लेन, नालियों, चौपालों और लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है। अन्य कार्यों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों, पुलियों और व्यक्तिगत शौचालयों के लिए भवनों का निर्माण शामिल है। सरकार ने वन अधिकारों (वन अधिनियम 2008), विस्थापन (आर एंड आर पॉलिसी), आजीविका (नरेगा) के संबंध में कुछ अच्छी कार्रवाई की है, सभी नक्सल जिले शामिल हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने राज्य के आसद्वार कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर अपनाया है। अतः इस मामले के रूप में संधेश के अध्ययन से नक्सलवाद को पराजित किया जा सकता है और विकास और नई सामाजिक व्यवस्था की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है लेकिन परिवर्तन को भीतर से आना होगा। झूलन देवी के रूप में लोग सबसे पहले नक्सलियों को अस्वीकार करना प्रारम्भ किया और दूसरे लोगों ने इनका अनुसरण किया और आज भी अनुसरण कर रहे है।

निष्कर्षः

माओवादी समस्या अभी भी बिहार के कई अन्य जिलों में पनप रही है। यह केवल वोट बैंक के राजनीतिक कारकों के कारण है। सभी राजनीतिक दल दलितों के वोट पाने की प्रत्याशा में माओवादी को लुभाने की होड़ में हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। वास्तव में, माओवादी राजनीतिक दल मतपत्र खो चुके हैं। यह केवल 1989 में आरा संसदीय सीट जीतने में कामयाब रहा। तब से इसका राजनीतिक स्थान तेजी से सिकुड़ गया है। लोगों ने राज्य में अपना

विश्वास दोहराया है और हिंसक प्रथाओं का खंडन किया है। अभी भी माओवादी के पूर्ण उन्मूलन पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। फिर भी, मध्य बिहार ने माओवादी ताकतों की गिरावट देखी है।

संदर्भः

1. भाटिया, बेला, **'एनाटॉमी ऑफ ए मस्क्रेः द नक्सली मूवमेंट इन सेंट्रल बिहार'**, सेमिनार, फरवरी 2000।
2. सुमंता, बनर्जी, **भारत की सिमरिंग क्रांतिः नक्सली विद्रोह**, दिल्ली, चयनित पुस्तक श्रृंखला, 1984।
3. जक्सा, जोहानी और महाकुल, बी.के., **'ट्राइब्स एंड नक्सलवाद'**, सोशल एक्शन, जुलाई–सितंबर 2010।
4. योजना आयोग, भारत सरकार के विशेषज्ञ गोपू रिपोर्ट।
5. ओटकेन, जेनिफर, **'भारत में नक्सलियों के खिलाफ प्रतिवाद'**, रूटलेज, 2009
6. Mishra, Trinath, "**Barrel of the Gun**", The Maoist Challenge and Indian Democracy, New Delhi, Sheriden Book, Company.
7. सिंह, प्रकाश, **भारत में नक्सली आंदोलन**, रूपा एंड कंपनी, 1996, पीपी 157–65।

IJOMRC